would like to ask what is the policy of the Government of India. If there is a policy, it is high time you recast your policy towards Sri Lanka. If you have a policy, I think, that policy is to collaborate the war in Sri Lanka, that is what is happening on ground. It so happens that there is confusion in India's foreign policy as far as Sri Lanka is concerned. Indian Government considers that what is going on in Sri Lanka is a war between Sri Lankan Government and the LTTE; it is an internal problem of another sovereign nation, so, India has a limited role. But I wish to underline that India cannot treat this problem just as an internal problem of a sovereign nation. We have more than 70 to 80 thousand refugees in Tamil Nadu. Who is responsible for these refugees? What is the policy of the UPA Government? The UPA Government is making a goody-goody statement whereas this Government has miserably failed to safeguard the lives of the innocent Sri Lankan Tamils. My humble request is that the Government comes up clean on its foreign policy towards Sri Lanka. I am asking the Rajapaksa Government to stop this war and find out a political solution to the problem. ...*(Interruptions)*... *(Time-bell rings)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja. ...*(Interruptions)*... Mr. Maitreyan, you have not given your name. ...*(Interruptions)*... Are you supporting it? ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, I will take only 30 seconds.

DR. V. MAITREYAN: The attack on Tamilians in Sri Lanka is a matter of serious concern. The war has to be stopped. The fatal attack by the Sri Lankan Army has to be stopped. In these efforts, whatever steps the Central Government takes AIADMK will definitely support. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): I would like to submit that, yesterday, the hon. President of India made it very clear about the Indian Government's policy on Sri Lanka. The hon. President very clearly said that there should be ceasefire and they should go to the negotiating table. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAY SINGH (Jharkhand): Sir, hospitals are bombarded. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: One thing I would like to say, Sir, at any cost our country. ...*(Interruptions)*...They have been kept as hostages by the LTTE militants. Our Government will not support the banned organisation, LTTE ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY SPEAKER: Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Government of India cannot behave like this. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Raja, please sit down.

Returning of medals by ex-army officers

सरदार तरलोचन सिंह (हरियाणा): डिप्टी चेयरमैन सर, मैं एक बहुत जरूरी मसले की ओर आपका और सारे हाऊस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 9 फरवरी को हमारे देश के तकरीबन 300 रिटायर्ड फौजी जरनल और वे

फौजी, जिन्हें बहुत से अवार्ड्स मिले हैं एवं उनकी पत्नियां मिल कर राष्ट्रपति भवन गए। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो मैडल इन फौजी भाइयों को बहादुरी के लिए मिले थे, वे उन्होंने वापस कर दिए। यह इसलिए हुआ क्योंकि पिछले दो महीने से हमारे एक्स-सर्विसमैन धरने पर जन्तर-मन्तर पर बैठे थे और उनकी डिमांड थी, "One Rank - One Pay". यह कितनी अजीब बात है कि एक तरफ सारा देश डिफैंस सर्विसिज़ की तरफ ध्यान देता है कि हमारी फौजी ताकत मज़बूत हो और दूसरी तरफ वे फौजी हैं, जिन्होंने हमेशा अपने देश के लिए जानें दीं, लेकिन उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है।

सर, हमारे देश में 35 लाख एक्स-सर्विसमैन हैं, जिनमें से तक़रीबन 19 लाख जवान हैं। यह बात सभी को पता है कि हमारे फौजियों की रिटायरमेंट early age में होती है। फौज का जवान 40 वर्ष की एज में रिटायर होता है और जो कर्नल और ब्रिगेडियर हैं, वे 50 और 55 की ऐज में रिटायर होते हैं। जब उनको अर्ली ऐज में रिटायर किया जाता है, तब उन्हें पेंशन के सिवाए और कुछ नहीं मिलता, लेकिन हुआ क्या है कि जितनी बार भी सरकार ने पेंशन के केसिज़ के लिए रूल्स बनाए हैं, अन्य सब सर्विसिज़ के लिए तो प्रावधान कर दिया गया, लेकिन एक्स-सर्विसमैन के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इसके कारण हुआ यह है कि डिफरेंट स्टेसिज़ पर जो सर्विसमैन रिटायर हुए, उनको डिफरेंट तरीके से पेंशन मिल रही है। कहीं पर कर्नल की पेंशन ज्यादा है तो मेजर जनरल की कम है, कहीं हवलदार की ज्यादा है तो उसके ऑफिसर की पेंशन कम है।

सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर एक्स-सर्विसमैन नाराज़ रहे, तो इसका असर सर्विंग सोल्जर्स पर भी पड़ता है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इनकी डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। इनकी डिमांड्स बहुत सिम्पल है कि सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाए, जैसा कि बाकी सर्विसिज़ में किया जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि इस इश्यू पर यह सरकार चुप क्यों बैठी है, जबकि सारे देश का ध्यान हमारी आर्मी की तरफ है। आर्मी की मज़बूती के साथ देश की मज़बूती है। हम इन सब फौजियों को सड़कों पर घूमते देख कर क्यों मौन हैं? वे अपने मैडल्स वापस कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल)ः सर, मैं इनके साथ इस विषय पर स्वयं को एसोसिएट करती हूं।

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल)ः सर, मैं भी इन्हें एसोसिएट करता हूं।

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश)ः सर, मैं स्वयं को इनके विषय से एसोसिएट करता हूं।

Construction of old age homes

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश)ः सर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के इश्तहार हम रोज देखते हैं और इश्तहारों में आता है कि वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनाए जाने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन पिछले दिनों यह मामला सामने आया है कि वृद्धाश्रम बनाने के लिए केन्द्र सरकार की जो योजना है, उसका सारा बजट बंद कर दिया है और उस मंत्रालय के मंत्री के नाम से ही यह बयान छपा है। मेरा कहना यह है यह देश वृद्धों का सम्मान करता है और इसके लिए सरकार की कुछ योजनाएं हैं। स्वयं आपने ही कहा है कि वृद्धाश्रम बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे।

हद तो तब हो गई, जब एक एनजीओ को मंत्रालय का पत्र पहुंचा कि ये जो सारी योजनाएं हैं, अब ये गैर योजनाओं में आ गई हैं, इसलिए आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। क्या सरकार वृद्धों का इसी तरह सम्मान करती